Withdrawal of privatisation of Insurance Industry Bill

685. PROF. RAM KAPSE:
SHRIMATI MALTI SHARMA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Mr. Lawrence Summers, Deputy Minister of Finance, U.S.A. has criticised Government of India for withdrawing the Bill regarding "Privatisation of Insurance Industry"; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN TH1-MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) Government has no such official information.

(b) Does not arise.

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन दर्ज किये गये मामले

686. **श्री चिमनभाई हरीभाई शुक्ल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन व्यक्तियों और संख्याओं के विरूद्ध कितने मामले दर्ज किये गये हैं और ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं की संख्या कितनी-कितनी है और उनसे जब्त की गई सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन देश के उद्योगपतियों के विरूद्ध दर्ज किये गये मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार "फेरा" के स्थान पर "फेमा" कानून लाने पर विचार कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो इतनी विशेषताओं और प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या प्रस्तावित नया "फेमा" कानून लागू होने से दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करना अधिक आसान होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान ली गई तलाशियों की संख्या एवं पकड़े माल का मूल्य इस प्रकार है:

वर्ष	ली गई तलाशियों की संख्या	पकड़ी गई विदेशी मुद्रा का मूल्य	पकड़ी गई भारतीय मुद्रा
1994	1540	314,26	974.78
1995	1175	541.34	1021.02
1996	1164	724.42	1083.16

(ख) दोषी व्यक्तियों की श्रेणी के अनुसार आंकड़े नही रखे जाते।

(ग) से (ङ) सरकार का विदेशी मुद्रा विनीयमन अधिनियम (फेरा) को विदेशी मुद्रा प्रबन्धक अधिनियम (फेमा) द्वारा का प्रस्ताव है।

Assessment of assets of industrial houses

687. SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that consequent upon the omission of Section 26 of the MRTP Act, 1969 by the MRTP (Amendment) Act, 1991, large industrial houses are no longer required to be registered with the Central Government;

(b) if so, how Government know and then assess the assets of industrial houses in the country; and

(c) if there is any source, then name the top one hundred industrial houses and the assets they hold;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Consequent upon deletion of part A of Chapter III of the MRTP Act, 1969 with effect from 27.09.1991, data on industrial houses are not compiled separately by the Department of Company Affairs.